jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

izkf/dkj ls izdkf'kr

la- 555] ubZ fnYyh] eaxyokj] vDrwcj 28] 2014@dk£rd 6] 1936

No. 555] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2014/KARTIKA 6, 1936

िवुत मं ालय

नई दली, 16 अूबर, 2014

अिधसूचना

(अ).—िवुत अिधनियम, 2003 िजसे इसम (इसके प"ात् इस अिधसूचना म उ अिधनियम कहा गया है) क+ धारा 83 क+ उपधारा (1) यह उपबंध करती है क (क) दो या उससे अिधक रा0य1 क+ सरकार1; या (ख) एक या उससे अिधक संघ शा िसत 4े51 के संबंध म क6ीय सरकार और एक या उससे अिधक रा0य1 क+ सरकार1 9ारा कए जाने वाले करार करके एक संयु आयोग का गठन कया जा सकेगा और यह ऐसी अविध के िलए =व>तत कया जायेगा और आगे क+ =?येक अविध यद कोई हो, के िलए नवीकरण के अधीन होगा जैसा करार म अनुबं@ कया जाए ।

और जब क क6ीय सरकार ने, क6ीय सरकार को ऐसा करने के िलए =ािधकृत करते Bए भागीदार रा0य सरकार1 9ारा एक समझौता Fापन (िजसे इस अिधसूचना म इसके प"ात् उ करार कहा गया है) हGता4Hरत करने के प"ात् उ अिधनियम क+ धारा 83 क+ उपधारा (5) के अधीन तारीख18 जनवरी, 2005 क+ अिधसूचना 9ारा मिणपुर और िमजोरम संयु के िलए िवुत िविनयामक आयोग का गठन कया था ।

और जब क उ अिधनियम क+ धारा 83 क+ उपधारा (5) के अधीन, क6ीय सरकार, यद सभी भागीदार रा0य1 9ारा इस =कार से =ािधकृत कया जाए, क वह एक संयु आयोग का गठन करे और उ अिधनियम क+ धारा 83 क+ उपधारा (3) के अधीन िनMदN सभी या कसी मामले के संबंध म शिय1 का =योग करे और जहां भागीदार रा0य1 9ारा िविनMदN Oप से वैसा करने केिलए =ािधकृत कया गया हो ।

और यह क उ करार के खPड (xxi) 9ारा मिणपुर और िमजोरम रा0य1 ने भारत सरकार को मिणपुर और िमजोरम रा0य1 के िलए संयु िवुत िविनयामक आयोग के गठन और संयु आयोग से संबंिधत उ अिधनियम के उपबंध1 के अनुपालन के िलए िनयमबनाने के िलए =ािधकृत कया है ।

4270 GI/2014 (1)

अतः अब िवुत अिधनियम, 2003 क+ धारा 104 और धारा 180 क+ उपधारा (2) के खPड (ज) के साथ पHठत धारा 83 क+ उपधारा (3) और उपधारा (5) 9ारा =दR शिय1 का =योग करते Bए क6ीय सरकार भारत के िनयं5क-महालेखापरी4क,के परामशS से िनTिलिखत िनयम बनाती है अथाSत् –

संि नाम और ारभ – (1) इन िनयम1 का संि4U नाम मिणपुर और िमजोरम रा0य संयु िवुत

िविनयामक आयोग (िनिध का गठन और उपयोजन क+ रीित और बजट तैयार करने के िलए =Oप और समय) िनयम,

2014 है ।

(2) ये राजप5 म =काशन क+ तारीख को =वृR ह1गे ।

2. परभाषाएं –

(1) इन िनयम1 म जब तक क संदभS म अWयथा अपेि4त न हो, -

(क) "लेखा अिधकारी" से ऐसा अिधकारी अिभ=ेत है जो संयु आयोग के अXय4 9ारा नामिनMदिशत

कए गए लेखे के अनुर4ण और वा>षक लेखे क+ तैयारी के िलए उRरदायी हो ।

(ख) "अिधिनयम" से िवुत अिधिनयम, 2003 (2003 का 36) अिभ=ेत है ।

(ग) "लेखापरी4ा अिधकारी" से भारत के िनयं5क-महालेखापरी4क या संयु आयोग के लेख1 क+

संपरी4ा के संबंध म उनके 9ारा िनयु कोई अिधकारी अिभ=ेत है ।

(घ) "अXय4" से मिणपुर और िमजोरम रा0य1 के िलए संयु िवुत िविनयामक आयोग का अXय4

अिभ=ेत है ।

(ङ) "िवRीय वषS" से वह अविध अिभ=ेतहै जो वषS के 01 अ=ैल से आरंभ होकर अगले वषS के 31 माचS

तक, बारह कैलेPडर वष[से अनािधक हो ।

(च) "=Oप" से इन िनयम1 के साथ संल\=Oपअिभ=ेत है ।

(छ) "संयु आयोग" से अिधिनयम क+ धारा 83 के अधीन गHठत मिणपुर और िमजोरम रा0य1 के िलए

संयु िवुत िविनयामक आयोग अिभ=ेत है ।

(ज) "सदGय" से मिणपुर और िमजोरम रा0य1 के िलए संयु िवुत िविनयामक आयोग का सदGय

अिभ=ेत है ।

(झ) "भागीदार रा0य" से मिणपुर रा0य और/या िमजोरम रा0य अिभ=ेत है ।

(ञ) "अनुसूची" से दी गई रािशय1 के ^यौरे दशाSते Bए इन िनयम1 के साथ संल\ अनुसूची अिभ=ेत है ।

(ट) "सिचव" से मिणपुर और िमजोरम रा0य1 के िलए संयु िवुत िविनयामक आयोग का सिचव

अिभ=ेत है ।

(2) उन सभी श^द एवं अिभ_िय1 का, जो इन िनयम1 म =युह` एवं पHरभािषत नहa क+ गई ह`,

कWतु िवुत अिधिनयम, 2003 (2003 का 36) म पHरभािषत ह`, का वहीअथS होगा जो उस

अिधिनयम म है ।

3. आयोग के लेखे

¹Hkkx II[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3

(1) संयु आयोग 2007-08 से =ारंभ कर =?येक िवR वषS के िलए वा>षक लेखा िववरण तैयार करेगा ।

(2) संयु आयोग का सिचव, संयु आयोग के एक अिधकारी को उनक+ ओर से लेखा तैयार करने के िलए =ािधकृत करेगा ।

(3) संयु आयोग का सिचव, संयु आयोग के लेखे के अनुर4ण, िवRीय िववरण और िववरिणका के संकलन का पयSवे4ण करेगा तथा सुिनि"त करेगा क संयु आयोग के लेखे क+ लेखा-परी4ा के उd े्य से लेखा परी4ा अिधकारी 9ारा अपेि4त संयु आयोग के सभी लेखे,बही, संब@ वाउचर तथा अWय दGतावेज और कागजात उस अिधकारी के िनपटान पर रखे जाएं ।

(4) संयु आयोग के सिचव 9ारा, संयु आयोग 9ारा िविधवत अनुमोदत तथा भारत के िनयं5क-महालेखापरी4क या उनके =ािधकृत =ितिनिध 9ारा =मािणत कए जाने के प"ात् वा>षक लेखा िववरण, क6ीय सरकार 9ारा यथािनधाSHरत तारीख तक क6ीय सरकार (संयु आयोग के =चालन के =थम पांच वषS के िलए) तथा भागीदारी रा0य सरकार1 (संयु आयोग के =चालन के छठ वषS से और उसके आगे से) को =Gतुत कया जायेगा ।

(5)

(क) संयु आयोग िनTिलिखत लेखेनीचे व>णत =Oप1 म तैयार करेगा –

=Oप क म =ािU और भुगतान लेखे;

=Oपख म आय और _य

लेखे;

(i) (ii) (iii) (ख)

(ग)

(घ)

संयु आयोग का सिचव "=ािU और भुगतान लेखा", "आय और _य लेखा" तथा "तुलन-प5" पर

हGता4र करने तथा अिध=मािणत करने के िलए =ािधकृत हGता4रकताS होगा ।

वा>षक लेखा िववरण संपरी4ा अिधकारी को लेखे से संबंिधत वषS के अगले वषS 30 जून को या इससे पहले =Gतुत कया जाएगा तथा संपरी4ा अिधकारी संयु आयोग के लेखे क+ संपरी4ा करेगा और उस पर HरपोटS देगा ।

संयु आयोग, लेखा परी4ा HरपोटS =ाU होने पर, उसम िनMदN क+गई कसी कमी या =Oप ग म तुलन-प5 ।

अिनयिमतता का सुधार करेगा और उस पर क+ गई कारSवाई के बारे म क6ीय सरकार तथा संपरी4ा अिधकारी को सूिचत करेगा ।

4. आयोग के वाषक लेखे क! तैयारी का $प और समय –

(क) संयु आयोग =?येक िवR वषS के िलए वा>षक लेखा िववरण नीचे दए गए रीित से तैयार करेगा और उसम िनTिलिखत सिgमिलत ह1गेः

(i) तुलन-प5;

(ii) आय और _य लेखा;

(iii) उपयुS िवRीय िववरण1 क+ अनुसूिचयां;

(iv) अनुदेश और लेखा िस@ांत;

(v) अनुसूिचय1 पर HटIपण और अनुदेश;

(vi) =ािU और भुगतान के िववरण।

(ख) संयु आयोग 9ारा वा>षक लेखा िववरण को लेखा से संबंिधत िवR वषS के प"ात् तीन मास क+ अविध के भीतर अंितम Oप दया जाएगा ।

(ग) वा>षक लेखा िववरण, संसदीय सिमित क+ िसफाHरश पर िनयु िवशेषF सिमित 9ारा तैयार कए गए Oप िवधान के अनुसार तैयार कया जाएगा ।

5. वाषक लेखा िववरण का अनुमोदन –

(क) िवR वषS क+ समािU के प"ात् तीन मास के भीतर, लेखािधकारी वा>षक लेखा िववरण तैयार करेगा और सिचव उसे संयु आयोग को अनुमोदन के िलए =Gतुत करेगा तथा संयु आयोग 9ारा अनुमोदन के प"ात्, वा>षक लेखा िववरण संपरी4ा के िलए िनयं5क-महालेखापरी4क को या उनके 9ारा िनयु कसी अWय _ि को भेजा जाएगा ।

(ख) संयु आयोग के लेखे अXय4, िवR से संबंिधत कायS करने वाले एक सदGय तथा संयु आयोग के सिचव 9ारा अिध=मािणत कए जायगे ।

6. लेखे के अिभलेख(का परीरण, इ+या,द –

(क) संयु आयोग इन िनयम1 के अधीन तैयार तुलन-प5, आय और _य लेखे तथा =ािU और भुगतान लेखे के अिभलेख1 को Wयूनतम दस वषS क+ अविध के िलएपHररि4त करेगा ।

(ख) बहीखात1 तथा अWय सुसंगत अिभलेख1 को संयु आयोग के कायाSलय म रखा जाएगा और यह सुिनि"त करने का दाियव लेखािधकारी का होगा क बहीखात1 तथा अWय संबंिधत अिभलेख1 का उिचत अनुर4ण कया जाए तथा सुरि4त अिभर4ा म संभाल कर रखा जाए और जब कभी अपेि4त हो, उसे संपरी4ा के िलए =Gतुत कया जाए ।

7. ािधकृत ह0तारकता1 –

तुलन-प5, आय और _य लेखे और =ािU और भुगतान लेखे पर िनदेशक (=शासन) या संयु आयोग 9ारा अिधकृत कसी अWय अिधकारी 9ारा हGता4र कए जाएंगे ।

[फा. सं. 47/1/2009-आर एPड आर]

0योित अरोरा, , , संयु सिचव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 16th October, 2014

NOTIFICATION

G.S.R 754(E).—Whereas sub-section (1) of section 83 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter in this notification referred to as the said Act) provides that a Joint Commission may be constituted by an agreement to be entered into (a)
by two or more Governments of States; or (b) by the Central Government, in respect of one or more Union territories,
and one or more Governments of States, and shall be enforced for such period and shall be subject to renewal for each
further period, if any, as may be stipulated in the agreement;

And whereas the Central Government had constituted a Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur
and Mizoram vide notification dated the 18th January, 2005 under sub-section (5) of section 83 of the said Act, after the
participating State Governments signed a Memorandum of Agreement (hereinafter in this notification referred to as the
said Agreement) authorizing the Central Government to do so;

And whereas sub-section (5) of section 83 of the said Act, the Central Government may, if so authorized by all the participating States, constitute a Joint Commission and may exercise the powers in respect of all or any of the matters
specified under sub-section (3) of section 83 of the said Act and when so specifically authorized by the participating

States;

[1]Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5

And whereas vide clause (xxi) of the said Agreement, the States of Manipur and Mizoram have authorized Government of India to constitute a Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram and to frame rules to carry out the provisions of the said Act relating to the Joint Commission;

Now, therefore,in exercise of powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 83 read with sections 104 and clause (h) of sub-section (2) of section 180 of the Electricity Act, 2003, the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement

(1) These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2014.

2. Definitions. -

(1) In these rules unless the context otherwise requires, –

(a) “Accounts Officer” means an officer responsible for maintenance of accounts and preparation of annual accounts as nominated by the Chairperson of the Joint Commission;

(b) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(c) “Audit Officer” means the Comptroller and Auditor-General of India or any officer appointed by him in connection with the audit of accounts of the Joint Commission;

(d) “Chairperson” means the Chairperson of the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram;

(e) “Financial year” means a period not exceeding twelve calendar months commencing on the 1st April of a year and concluding on the 31st March of the subsequent year;

(f) “Form” means a form appended to these rules;

(g) “Joint Commission” means the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram constituted under section 83 of the Act;

(h) “Member” means a Member of the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram;

(i) “Participating State” means the State of Manipur and/or the State of Mizoram;

(j) “Schedule” means the schedule appended to these rules showing details of the amounts given;

(k) “Secretary” means the Secretary of the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram.

(2) All the words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), shall have the meanings assigned to them in that Act.

3. Accounts of the Commission. -

(1) The Joint Commission shall prepare the annual statement of accounts for every financial year

commencing with 2007-08.

(2) The Secretary of the Joint Commission may authorise an officer of the Joint Commission to prepare the account on his behalf.

(3) The Secretary of the Joint Commission shall supervise the maintenance of the accounts of the Joint Commission, the compilation of financial statement and return, and shall ensure that all accounts, books, connected vouchers and other documents and papers of the Joint Commission required by the audit officer for the purpose of auditing the accounts of the Joint Commission are placed at the disposal of that officer.

(4) The annual statement of accounts duly approved by the Joint Commission and after certification by the Comptroller and Auditor-General of India or his authorised representative, shall be submitted by the Secretary of the Joint Commission to the Central Government (for the first five years of operation of the Joint Commission) and the Participating State Governments (from the sixth year of operation of the Joint Commission onwards)by such date as may be specified by the Central Government.

(5)

(a) The Joint Commission shall prepare the following accounts in the forms mentioned below -

(i) the Receipt and Payment Accounts in Form A;

(ii) the Income and Expenditure Accounts in Form B;

(iv)the Balance Sheet in Form C.

(b) The authorised signatory to sign and authenticate the “Receipt and Payment Accounts”, “Income and Expenditure Accounts” and “Balance Sheet” shall be the Secretary of the Joint Commission.

(c) The annual statement of accounts shall be submitted to the Audit Officer on or before the 30th June following the year to which the accounts relate and the Audit Officer shall audit the accounts of the Joint Commission and report thereon.

(d) The Joint Commission shall, on receipt of the audit report, correct any defect or irregularity pointed out therein and report to the Central Government and the Audit Officer about the action taken by it thereon.

4. Form and time of preparation of Annual Accounts of the Commission. -

a) The Joint Commission shall prepare the Annual Statement of Accounts for every financial year in the manner specified below and shall comprise:

(i) the Balance Sheet;

(ii) the Income and Expenditure Account;

(iii) the Schedules to the above financial statements;

(iv) the instructions and accounting principles;

(v) the notes and instruction from the Schedules

(vi) the Statements of Receipts and Payments.

(b) The Annual Statement of Accounts shall be finalised by the Joint Commission within a period of three months following the financial year to which the accounts relate.

(c) The Annual Statement of Accounts shall be prepared as per the format devised by the Committee of Experts appointed on the recommendation of the Parliamentary Committee.

5. Approval of the Annual Statement of Accounts. -

(a) Within three months after the end of the financial year, the Accounts Officer shall prepare and the Secretary shall submit the Annual Statement of Accounts to the Joint Commission for approval and on

approval by the Joint Commission, the Annual Statement of Accounts shall be sent to the Comptroller and

Auditor-General or any other person appointed by him for audit.

(b) The Accounts of the Joint Commission shall be authenticated by the Chairperson, one Member dealing

with the Finance and the Secretary of the Joint Commission.

6. Preservation of records of accounts, etc. -

(a) The Joint Commission shall preserve the records of Balance sheet, Income and Expenditure Accounts and

Receipts and Payments account prepared under these rules for a minimum period of ten years.

(b) The books of accounts and other relevant records shall be kept in the Joint Commission's office and it shall

be the responsibility of the Accounts Officer to ensure that the books of accounts and other relevant records are properly maintained and securely preserved in safe custody and produced to Audit as and when

required.

7. **Authorized signatory. -**

The Balance Sheet, the Income and Expenditure Accounts and the Receipts and Payments Account shall be signed by the Director (Admn) or any other Officer authorised by the Joint Commission.

[F.No. 47/1/2009-R&R]

[1]Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

नई दली, 16 अूबर, 2014

अिधसूचना

(अ).—िवुत अिधिनयम, 2003 िजसे इसम (इसके प"ात् इस अिधसूचना म उ अिधिनयम कहा गया है) क+ धारा 83 क+ उप-धारा (1) यह उपबंध करती है क (क) दो या उससे अिधकरा0य1 क+

सरकार1; या (ख) एक या उससे अिधक संघ शािसत 4े51 के संबंध म क6ीय सरकार और एक या उससे अिधक रा0य1

क+ सरकार1 9ारा कए जाने वाले करार करके एक संयु आयोग का गठन कया जा सकेगा और यह ऐसी अविध के िलए =व>तत कया जायेगा और आगे क+ =?येक अविध यद कोई हो, के िलए नवीकरण के अधीन होगा जैसा करार म अनुबं@ कया जाए ।

और जब क क6ीय सरकार ने, क6ीय सरकार को ऐसा करने के िलए =ािधकृत करते Bए भागीदार रा0य सरकार1 9ारा एक समझौता Fापन (िजसे इस अिधसूचना म इसके प"ात् उ करारकहा गया है) हGता4Hरत करने के प"ात् उ अिधिनयम क+ धारा 83 क+ उपधारा (5) के अधीन तारीख18 जनवरी, 2005 क+ अिधसूचना 9ारा मिणपुर और िमजोरम संयु के िलए िवुत िविनयामक आयोग का गठन कया था ।

और जब क उ अिधनियम क+ धारा 83 क+ उपधारा (5) के अधीन, क6ीय सरकार, यद सभी भागीदार रा0य1 9ारा इस =कार से =ािधकृत कया जाए, क वह एक संयु आयोग का गठन करे और उ अिधनियम क+

धारा 83 क+ उप-धारा (3) के अधीन िनMदN सभी या कसी मामले के संबंध म शिय1 का =योग करे और जहां

भागीदार रा0य1 9ारािविनMदN Oप से वैसा करने के िलए =ािधकृत कया गया हो ।

और यह क उ करार के खPड (xxi) 9ारा मिणपुर और िमजोरम रा0य1 ने भारत सरकार को मिणपुर और

िमजोरम रा0य1 के िलए संयु िवुत िविनयामक आयोग के गठन और संयु आयोग से संबंिधत उ अिधनियम केउपबंध1 के अनुपालन के िलए िनयम बनाने के िलए =ािधकृत कया है ।

अतः अब िवुत अिधनियम, 2003 क+ धारा 103, धारा 106 और धारा 180 क+ उपधारा (2) के खPड

(छ) और (ञ) के साथ पHठत धारा 83 क+ उप धारा (3) और उप धारा (5) 9ारा =दR शिय1 का =योग करते Bए

क6ीयसरकार भारत के िनयं5क-महालेखापरी4क, के परामशS से िनTिलिखत िनयम बनाती है अथाSत् –

संि नाम और ारभ – (1) इन िनयम1 कासंि4U नाममिणपुर और िमजोरम रा0य संयु िवुत िविनयामक आयोग (िनिध का गठन और उपयोजन क+ रीित और बजट तैयार करने के िलए =Oप और समय) िनयम, 2014 है ।

(2) ये राजप5 म =काशन क+ तारीख को =वृR ह1गे ।

परभाषाएं (1) इन िनयम1 म, जब तक क सWदभS से अWयथा अपेि4त न ह1-

(क) "लेखा अविध" से ऐसी अविध अिभ=ेत है िजसके िलए लेखा संयु आयोग 9ारा तैयार कए जायगे और

िवRीय वषS के समवतk ह1गे;

(ख) "अिधनियम' से िवुत अिधनियम, 2003 (2003 का 36) अिभ=ेत है;

(ग) "बजट" से अिधनियम क+ धारा 106 के अनुसार संयु आयोग 9ारा तैयार क+ गई =ाlिलत आय और

_य अिभ=ेतहै ।

(घ) "अXय4" से मिणपुर और िमजोरम रा0य संयु िवुत िविनयामक आयोग का अXय4 अिभ=ेत है ।

(ङ) "आहरण और संिवतरण अिधकारी" से संयु आयोग 9ारा नाम िनMदN ऐसा अिधकारी अिभ=ेत है जो संयु आयोग क+ ओर से आहरण करे और भुगतान करे ।

(च) "िवRीय वषS" से कसी वषSक+ पहली अ=ैल से आरgभ होकर 12 कैलेPडर मास से अनिधक अविध और अनुवतk वषS के 31 माचS को समाU होने वाली अविध, अिभ=ेत है;

(छ) "=Oप" से इन िनयम1 से संल\ कोई =Oप अिभ=ेत है;

(ज) "िनिध" से मिणपुर और िमजोरम रा0य संयु िवुत िविनयामक आयोग क+ िनिध अिभ=ेत है;

(झ) "संयु आयोग" से अिधनियम क+ धारा 83 क+ उप-धारा (5) के अधीन गHठत मिणपुर और िमजोरम रा0य संयु िवुत िविनयामक आयोग अिभ=ेत है ।

(ञ) "सदGय" से मिणपुर और िमजोरम रा0य संयु िवुत िविनयामक आयोग केसदGय अिभ=ेत है ।

(ट) "भागीदार रा0य " से मिणपुर और िमजोरम रा0य अिभ=ेत ह` ।

(ठ) "सिचव" से मिणपुर और िमजोरम रा0य संयु िवुत िविनयामक आयोग का सिचव अिभ=ेत है

। 2. उन श^द1 और पद1 का, जो इन िनयम1 म =यु है और पHरभािषत नहa है कWतु िवुत अिधनियम, 2003 मपHरभािषत है, वही अथS होगा जो mमशः उस अिधनियम म है ।

3. िनिध का गठन

(1)

केW6ीय सरकार के मिणपुर और िमरोजम रा0य संयु िवुत िविनयामक आयोग िनिध नामक एक िनिध का गठन करती है ।

(2) िनिध, भारतीय लोक लेखा के अधीन खोली जाएगी और यह एक _पगत न होने वाला और ^याज रिहत लेखा होगा ।

(3) इस िनिध म िनTिलिखत समािवN होगा –

(i)अिधनियम क+ धारा 102 के अधीन भागीदार रा0य1 9ारा केW6ीय सरकार के साथ हGता4Hरत करार Fापन के अनुसरण म केW6ीय सरकार 9ारा संयु आयोग को दया गया कोई अनुदान और ऋण तथा भागीदार रा0य सरकार1 9ारा संयु आयोग को दया गया कोई अनुदान और ऋण;

(ii)अिधनियम के अधीन संयु आयोग 9ारा =IU सभी फ+स;

(iii)केW6ीय सरकार 9ारा समय-समय पर िविनि"त अWय oोत1 से संयु आयोग 9ारा =IU सभी रािशयां; िनिध का उपयोजन – िनिध का उपयोजन िनTिलिखत को पूरा करने के िलए कया जाएगा–

(क) संयु अयोग के अXय4, सदGय1, सिचव, अिधकाHरय1 और अWय कमSचाHरय1 के वेतन, भRे और अWय पाHRpिमक;

(ख) अिधनियम क+ धारा 86 के अधीन संयु आयोग के कृ?य1 के िनवSहन म उसके _य;

(ग) अिधनियम 9ारा =ािधकृत उdेeय1 और उसके =योजन1 के िलए _य

[1]Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9

5. िनिध से रकम का जारी ,कया जाना

(1) संयु आयोग कसी िवRीय वषS म अपने वा>षक बजट के संबंध म िनिध से रकम जारी करने क+ दोबार (अ=ैल और िसतgबर मास म) मांग करेगा और संयु आयोग से ऐसी अXयपे4ा के =IU होने पर –

(क) केW6ीय सरकार िनिध म िवुत मं5ालय के वा>षक बजट म संसद 9ारा अनुमोदत संयु आयोग के िलए अनुदान1 और ऋण1 क+ रकम के समुिचत भाग को अंतHरत करेगी;

(ख) भागीदार रा0य सरकार िनिध म संबंिधत रा0य िवधानमPडल 9ाराअनुमोदत संयु आयोग के िलए अनुदान1 और ऋण1 को अंतHरत करेगी;

(ग) केW6ीय सरकार अपने वेतन और लेखा कायाSलय के माXयम से पाने वाले के खाते म देय चैक 9ारा संयु आयोग को िनिध से यथा अXयपेि4त रकम साथ-साथ जारी करेगी ।

(2) संयु आयोग इस िनिमत केW6ीय सरकार 9ारा िवशेष Oप से उिलिखत रीित म अनुदान1 और ऋण1 के उिचत लेखे और अWय अिभलेख रखेगा ।

(3) िवRीय वषS क+ समािU पर संयु आयोग आरंिभक अिधशेष, िनिध से =IU रकम (अनुदान1 और ऋण1 क+ रकम सिहत) और उपयोिजत और अनुपयोिजत अितशेष का उसम कथन करते Bए एक उपयोजन =माण-प5 =Gतुत करेगा ।

6. िनिध का उपयोजन करने क! रीित

(1) अिधनियम क+ धारा, 86 के अधीन संयु आयोग अपने कृ?य1 के िनवSहन के संबंध म और अिधनियम 9ारा =ािधकृत उdेeय1 और =योजन1 को पूरा करने के िलए अपेि4त _य करेगा ।

(2) ब5क खाते का खोला जाना

(क) आयोग का पूणS िविन"यके प"ात संयु आयोग कसी राqीकृत वािणि0यक ब`क म िनिध के िलए मुrय खाता खोलने और उसका रख-रखाव करेगा तथा जैसा क संयु आयोग उपयु समझे, ऐसे ब`क1क+ अWय शाखाsमसहायक खात1 का रख-रखाव करेगा ।

(ख) संयु आयोग नाम िनMदN ब`क या ब`क1 म उनक+ जानकारी और अिभलेख1 के िलए =ािधकृत हGता4रकताSs के Oप म अपने दो अिधकाHरय1 के हGता4र के नमूने उपल^ध कराएगा ।

(ग) नािमनMदN ब`क या ब`क1संयु आयोग को दैिनक संदाय और =ािU सूची =Gतुत करेगी जो यह सुिनि"त करेगी क संदाय सूची म उपद>शत चैक ऐसे ह` जो संयु आयोग 9ारा जारी कए गए ह` और ब`क1 के साथ =?येक सं_वहार का समाधान करेगी ।

(3) ब5क(से िनिधय(के आहरण

(क) अXय4 9ारा समय-समय पर नाम िनMदNकए गए संयु आयोग के आहरण और संिवतरण अिधकारी जो उप सिचव Gतर के नीचे का न हो, के 9ारा िनिध =चािलत क+ जाएगी ।

(ख) आहरण और संिवतरण अिधकारी और संयु आयोग 9ारा नाम िनMदNएक अWय अिधकारी 9ारा हGता4Hरत चैक के =Gतुत करने के प"ात ही ब`क खाते से आहरण कया जाएगा ।

(ग) आहरण और संिवतरण अिधकारी संयु आयोग क+ ओर से रसीद1 और भुगतान1 के समुिचत लेन-देन क+ िनगरानी करने के िलए िजgमेदार ह1गे ।

(घ) आहरण और संिवतरण अिधकारी, =?याियत ब`क1 म जमा कए गए चैक1/िडमांड tाuट क+ रािश जो संयुआयोग के खाते म समय पर जमा क+ जा चुक+ है और उनके साथ रसीद1 और भुगतान कए गए खात1 से िमलान भी कया गया है, को सुिनि"त करने के िलए िजgमेदार ह1गे ।

7. बजट

(1) बजट का आवत1न और तैयारी

संयु आयोग अपना बजट तैयार करेगा िजसम आगामी िवRीय वषS के िलए आयोग क+ अनुमािनत =ािU और _य का वा>षक िवRीय िववरण होगा ।

(2) संयु आयोग 9ारा =ितवषS िसतgबर के अWत तक आगामी िवRीय वषS का बजट तैयार कया जाएगा और

अिधिनयम क+ धारा 106 के अनुसार इसक+ अनुमािनत =ािUय1 को Xयान म रखने के प"ात कW6ीय सरकार को अvेिषत क+ जाएगी ।

(3) केW6ीय सरकार, संयु आयोग 9ारा दी गई सूचना के अनुसार आवeयकताs को सgयकOप से Xयान म रखने के प"ात संसद 9ारा कएगए िविनयोग के प"ात संयु आयोग को आवeयकतानुसार ऐसी रािश का अनुदान और ऋण दे सकती है ।

$प और सारांश

उपाबंध-1 पर दए गए Oप िवधानम =ाIिलत =ािU और _य और उपाबंध-2 म अंितम अनुदान का ^यौरा देते Bए संयु आयोग के बजट म चालू वषS के पुनरीि4त =ाIलन और अगले वषS के िलए बजट =ाIलन सिgमिलत होगा और mमशः =?येक िवRीय वषS के 30 िसतgबर और 15 जनवरी तक उWह केW6ीय सरकार को =Gतुत कया जाएगा ।

9. लेखे

(1) मिणपुर और िमजोरम रा0य संयु िवुत िविनयामक आयोग (लेख1 और अिभलेख1 के वा>षक िववरण का

=Oप) िनयम, 2014 के उपबंध1के अनुसार िनिध के लेख1 का रख-रखाव कया जाएगा ।

(2) अXय4, िवR को देखने वाले एक सदGय और आयोग के सिचव 9ारा संयु आयोग के खाते को अिध=मािणत कया जाएगा ।

लेखा7 क! संपरीा

(1) भारत के िनयं5क-महालेखापरी4क 9ारा ऐसे अंतराल1 पर जैसा उसके 9ारा िविनMदN कया जाए संयु आयोग के लेखाs क+ संपरी4ा क+ जाएगी ।

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11

(2) भारत के िनयं5क-महालेखा परी4क 9ारा या इस िनिमत उसके 9ारा िनयु कोई अWय _ि 9ारा यथा=मािणत संयु आयोग के लेखे, संपरी4ा HरपोटS के साथ (संयु आयोग के =चालन के =ारंिभक पाँच वष[के िलए) और भागीदार रा0य सरकार1 को (संयु आयोग के =चालन के छठे वषS और उसके आगे से) संयु आयोग 9ारा केW6ीय सरकार को संसद के =?येक सदन और भागीदार रा0य िवधान-मPडलके सम4 संपरी4ा HरपोटS को रखने के िलए उसे समथS बनाने के िलए =ितवषS भेजे जाएग ।

11. शि9य(का +यायोजन

(1) संयु आयोग के अXय4 को, िनTिलिखत िवषय1 को छोड़कर िवRीय शिय1 के =?यायोजन िनयम 1978 के िनयम 13, साधारण िवRीय िनयम, 2005 और साधारण भिवyय िनिध (केW6ीय सेवाएं) िनयम, 1960 के साथ पHठत अनुसूची 5 और अनुसूची 6 म दी गई मद1 से संबंिधत केW6ीय सरकार के कसी िवभाग को दी गई शियां सिgमिलतह1गी ।

(क) पद1 का सृजन;

(ख) एक शीषS से दूसरे शीषS म िनिधय1 का पुनःिविनयोग;

(ग) यान1का mय;

(घ) हािन को बzे खाते म डालना;

(ङ) िवदेश म संगोि{य1, सgमेलन1 या =िश4ण कायSmम म भाग लेने के िलए आयोग के कसी अिधकारी को अनुमित देना;

परWतु यह क इन शिय1 का =योग िवRीय शि का =?यायोजन िनयम, 1978 और अWय साधारण िनयम1 म अंत>वN साधारण िनबंधन1 और शत[तथा भारत सरकार 9ारा समय-समय पर जारी कए गए आदेश1 के अXयधीन होगा ।

(2) संयु आयोग िविभ| _य1 क+ मंजूरी और संयु आयोग, संयु आयोग के अXय4 और सिचव के बीच शि के =?यायोजन के िलए िवGतृत =mया को अिधकिथत करेगा ।

12. िनिध का समापन

(1) जब तक अिधिनयम के संगत लागू रहगे तब तक िनिध का =चालन जारी रहेगा ।

(2) िनिध के समापन के समय पर जब िनिध क+ और आवeयकता नहa होती है तब िनिध के अंतगSत खचS नहa क+ गई रािश को सरकारी खजाने म जमा कराना होगा ।

[फा. सं. 47/1/2009-आर एPड आर]

0योित अरोरा, , , , संयु सिचव

उपाबंध-I चालू वष1)))) के पुनरीित ा<लन

अगले वष1)))) के बजट ा<लन

(िनयम 8 देख?)

(बजट ा लन और पुनरीि#त ा लन) के बीच अंतर
(12-11)
लेखा शीष
िपछले 6 मास का ा लन1 (अंितम वष) 10 िपछले दो वष के वातिवक2
14
3 कुल पुनरीि#त
ा लन

अिBतम अनुदान िववरण
(िवCीय वष1)
आबंटन
1
1

ब
ज
ट

4

(िनयम 8 देख?)
थम 6 मास के वातिवक (पूव वत 2
वष5 और अंितम वष) बजट ा
लन6
12 अंतर के
कारण 15
7

आबंटन और पुनरीि#त ा लन के बीच अंतर (11-14) वातिवक (पूव वत 2 वष) िपछले 6 मास के िलए 8

उपा
बंध-
IIIII
II
9

टAपण 1. लेखा शीषS पHरिशN क पर सूची के अनुसार ह1गे।

टAपण 2. बजट उपबंध1 को पHरिशN ख पर यथा सूचीब@ िवGतृत Fापन के साथ GपN कया जाएगा।

लेखावणSन

Gापन 0तुत करेगा लेखा शीष1 ्I(पुनरी#त आबंटन 2 थम 10 मासके वातिवक3 पिछले 2 मास क)

अपे#ा4 संयु9आयोग बजट िववरण(और उसके 0पDकारी कुल अंितम अनुदान 5 शु* बचत/

आिध-य6 /ट0पणी7 परिशD-क

कोड

राज0व

2. फ!स और भार

2.1 फ+स

2.2 =भार

2.3 जुमाSने

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13

योग

2.4 अWय (िविनMदN कर)

कुल योग

3. अनुदान

3.1 सरकार से

3.2 अWय से

योग

4. दान

5. संगोIयां और समेलन

6. काशन(का िवJय

7. िविनधान(पर आय और

िनेप

7.1 िविनधान1 पर आय

7.2 िन4ेप1 पर आय

8. उधार

8.1 सरकार से

8.2 अWयसे (िविनMदN कर)

9. आिGतय1 का िवmय

10. िविनधान1 का िवmय

11. वेतन िबल1 से वसूिलयां

11.1 उधार1 और अिvम1 क+

मूल रकम

11.2 उधार1 और अिvम1 पर

^याज

12. =क+णS आय

12.1 आिGतय1 के िवmय पर

अिभलाभ

12.2 कोई अWय (िविनMदN

कर)

Kय

13. अXय4 और सदGय

13.1 वेतन और भRे

13.2 अWय फायदे
13.3 या5ा _य
13.3.1 िवदेश
13.3.2 घरेलू
14. अिधकारी
14.1 वेतन और भRे
14.2 सेवािनवृिR
फायदे
14.3 अWय फायदे
14.4 या5ा _य
14.4.1 िवदेश
14.4.2 घरेलू
15. कमSचाHरवृंद
15.1 वेतन और भRे
15.2 सेवािनवृिR
फायदे
15.3 अWय फायदे
15.4 या5ा _य
15.4.1 िवदेश
15.4.2 घरेलू
16. वाहन-भाड़ा
17. मजदूरी
18. अितकाल
19. मानदेय
20. अWय कायाSलय
_य
21. अनुसंधान पर_य
22. परामशSफ+स
23. संगोि{यां और
सgमेलन
24. संयुआयोग के
=काशन
25. कराया और कर
26. उधार1 पर ^याज
27. =वतSन संबंधी _य
28. सदGयता फ+स
29. अिभदान
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15
30. िGथर आिGतय1 का mय
31. िविनधान और िन4ेप
31.1 िविनधान
31.2 िन4ेप

32. =ितभूित िन4ेप

33. उधार और अिvम

33.1 कमSचाHरय1 को

33.1.1 ^याज सिहत

33.1.2 ^याज रिहत

33.2 =दायकताSs और ठेकेदार1 को

33.3 अWय (िविनMदN कर)

34. उधार1 का =ितसंदाय

35. अWय

35.1 छुzी वेतन और पशन अिभदाय

35.2 संपरी4ाफ+स

35.3 =क+णS

36. वणSन

37. आिGतय1 के िवmय पर हािन

38. बzे खाते म डाले गए डूबंत ऋण

39. डूबंत और शंकाGपद ऋण1 के िलए उपबंध

योग

परि

शD-ख मिणपुर और िमजोरम राLय(के िलए संयु9आयोग के पुनरीित ा<लन पूवSवतk वषS म वाGतिवक Gथापन पद संrया और उसक+ लागत सिहत =ाIलन म उसके िलए चाहे गए उपबंध सिहत Gथापन के pेणीवार ^यौरे द>शत करने वाला िववरण ।

मूल लागत, पुनरी4ण, यद कोई हो, को उपद>शत करते Bए पांच लाख से अिधक क+ लागत वाली एकल पHरयोजनाs/परामश[के =ाIलन और बजट अनुदान1 म पHरयोजना के िलए चाहे गए उपबंध ।

1.बजट/पुनरीि4त =ाIलन1 म िवदेशी मु6ा घटक के ^यौरे ।

2.बजट वषSऔर पूवSवतk वषS म राजGव =ािUय1 के =ाIलन ।

3.बजट वषS और पूवSवतk वषS के िलए संयुआयोग के िवRीय पHरणाम1 को द>शत करने वाला िववरण ।

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 16th October, 2014

NOTIFICATION

G.S.R. 755(E).— Whereas sub-section (1) of Section 83 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter in this notification referred to as the said Act) provides that a Joint Commission may be constituted by an agreement to be entered into (a) by two or more Governments of States; or (b) by the Central Government, in respect of one or more Union territories, and one or more Governments of States, and shall be enforced for such period and shall be subject to renewal for each further period, if any, as may be stipulated in the agreement;

And whereas the Central Government had constituted a Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram *vide* notification dated the 18th January, 2005 under sub-section (5) of Section 83 of the said Act, after the participating State Governments signed a Memorandum of Agreement (hereinafter in this notification referred to as the said Agreement) authorizing the Central Government to do so;

And whereas sub-section (5) of Section 83 of the said Act, the Central Government may, if so authorized by all the participating States, constitute a Joint Commission and may exercise the powers in respect of all or any of the matters specified under sub-section (3) of Section 83 of the said Act and when so specifically authorized by the participating States;

And whereas *vide* clause (xxi) of the said Agreement, the States of Manipur and Mizoram have authorized Government of India to constitute a Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram and to frame rules to carry out the provisions of the said Act relating to the Joint Commission;

Now, therefore,in exercise of powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 83 read with Sections 103, 106 and clause (g) and(j)of sub-section (2) of Section 180 of the Electricity Act, 2003, the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram (Constitution and the manner of application of the Fund and Form and Time for Preparation of Budget) Rules, 2014.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Accounting period" means the period for which the accounts have to be prepared by the Joint Commission and shall be concurrent with the financial year;

(b) "Act" means the Electricity Act, 2003(36 of 2003);

(c) "Budget" means the statement of estimated income and expenditure of the Joint Commission prepared as per section 106 of the Act;

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram.

(e) "Drawing and Disbursing Officer" means an officer designated as such by the Joint Commission to draw and make payments on behalf of the Joint Commission;

(f) "Financial Year" means a period not exceeding twelve calendar months commencing on the 1st April of a year and concluding on the 31st March of the subsequent year;

(g) "Form" means a form appended to these rules;

(h) "Fund" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram Fund;

(i) "Joint Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram constituted under sub-section (5) of section 83 of the Act;

(j) "Member" means a member of Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17

(k) "Participating State" means the State of Manipur and the State of Mizoram;

(l) "Secretary"' means Secretary of Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram.

(2) All the words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Constitution of the Fund. -

(1) The Central Government hereby constitutes a Fund to be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram Fund.

(2) The Fund shall be opened under the Public Account of India and this shall be a non-lapsable and non-interest bearing account.

(3) The Fund shall comprise of the following –

(i) any grants and loans made to the Joint Commission by the Central Government pursuant to the Memorandum of Agreement signed by the Participating States with the Central Government and any grants and loans made to the Joint Commission by the Participating State Governments under section 102 of the Act;

(ii) all fees received by the Joint Commission under the Act;

(iii) all sums received by the Joint Commission from other sources as may be decided upon by the Central

Government from time to time.

4. **Application of the Fund.** - The Fund shall be applied for meeting -

(a) the salary, allowances and other remuneration of the Chairperson, Members, Secretary, Officers and other employees of the Joint Commission;

(b) the expenses of the Joint Commission in discharge of its functions under section 86 of the Act;
and

(c) the expenses on objects and for the purposes authorised by the Act.

5. **Release of amount from the Fund. -**

(1) The Joint Commission shall seek release of amount from the Fund against its annual budget twice (in

the month of April, and September) in a financial year and upon receiving such a requisition from the Joint Commission -

(a) the Central Government shall transfer the appropriate part of the sums of grants and loans for the Joint

Commission approved by the Parliament in the annual budget of the Ministry of Power to the Fund;

(b) the Participating State Governments shall transfer the sums of grants and loans for the Joint

Commission approved by the respective State Legislatures to the Fund;

(c) the Central Government shall simultaneously release the amount as requisitioned from the Fund to the

Joint Commission by account payee cheque through its Pay and Accounts Office.

(2) The Joint Commission shall maintain proper accounts and other records of the grants and loans in the

manner as may be specified by the Central Government in this behalf.

(3) At the close of Financial Year, the Joint Commission shall furnish a utilisation certificate stating therein

the opening balance, amount (including of grants and loans) received from the Fund and utilised and the balance remaining unutilised.

6. **Manner of applying the funds**.-

(1) The Joint Commission shall meet expenses required in connection with the discharge of its functions

under section 86 of the Act and also for meeting objects and purposes authorised by the Act.

(2) **Opening of Bank Account -**

(a) The Joint Commission shall after taking a decision of the full commission to open the main account of the fund to be maintained in a Nationalised commercial bank and subsidiary accounts shall be maintained at such other branches of such banks as the Joint Commission considers appropriate.

(b) The Joint Commission shall make available the specimen signatures of two of its officers to the authorised signatory to the nominated bank or banks for their information and record.

(c) The nominated bank or banks shall furnish daily payments and receipts scrolls to the Joint Commission which shall ensure that the cheques appearing in the payment scrolls are those issued by the Joint Commission and reconcile each transaction with the banks.

(3) **Drawal of funds from the banks -**

(a) The Fund shall be operated by the drawing and disbursing officer of the Joint Commission not below the rank of Deputy Secretary, as may be designated by the Chairperson from time to time.

(b) The withdrawal from the bank account shall be made only on presentation of cheque signed by the Drawing and Disbursing Officer and one other officer designated by the Joint Commission.

(c) The Drawing and Disbursing Officer shall be responsible for monitoring the proper transactions of receipts and payments on behalf of the Joint Commission.

(d) The Drawing and Disbursing Officer shall be responsible to ensure that the amount of cheques and demand drafts deposited in the accredited banks have been timely credited in the accounts of the Joint Commission and shall also reconcile the receipts and payments accounts with them.

7. Budget. -

(1) Periodicity and preparation of Budget -

The Joint Commission shall prepare its budget which shall be the annual financial statement of the estimated receipts and expenditure of the Commission for the ensuing financial year.

(2) The Budget for the ensuing financial year shall be prepared by the Joint Commission by the end of September every year and forwarded to the Central Government, after taking into account its estimated receipts, vide section 106 of the Act.

(3) The Central Government may, after due appropriation made by the Parliament, make to the Joint Commission grants and loans of such sums of money as considers necessary, after having due regard to the requirement as communicated by the Joint Commission.

8. **Form and content of the Budget. -**

The Budget of the Joint Commission shall include the Revised Estimates of the current year and the Budget Estimates for the next year, giving details of estimated receipts and expenditure in the format as at Annexure-I and Final grant as at Annexure-II and submit them to the Central Government by the 30th September and the 15th January of each financial year respectively.

9. Accounts. -

(1) The accounts of the Fund shall be maintained as per the provisions of the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2014.

(2) The accounts of the Joint Commission shall be authenticated by the Chairperson, one Member dealing with the finance and the Secretary of the Commission.

10. Audit of the Accounts. -

(1) The accounts of the JointCommission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him.

(2) The accounts of the Joint Commission as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with audit report thereon shall be forwarded annually to the

Central Government (for the first five years of operation of the Joint Commission) and to the Participating State Governments (from the sixth years of operation of the Joint Commission onwards*)* by the JointCommission to enable it to place the audit report before each House of Parliament and the Participating State Legislatures.

11. Delegation of Powers. -

(1) The Chairperson of the Joint Commission shall have the powers of a Department of the Central Government relating to items as given in schedule V and schedule VI read with rule 13 of Delegation of Financial Powers Rules 1978, the General Financial Rules 2005and the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960, except in the following matters -

(a) Creation of posts;

(b) re-appropriation of funds from one head to another;

(c) purchase of vehicles;

(d) write off of loss; and

(e) permitting any officer of the Commission to participate in seminars, conferences or training programme

abroad:

Provided that the exercise of these powers shall be subject to the general restrictions and conditions contained in

the Delegation of Financial Power Rules, 1978 and other general rules and orders issued by the Government of India from

time to time.

(2) The Joint Commission shall lay down the detailed procedure for sanction of various expenditure and

delegation of power among the Joint Commission, Chairman and Secretary of the JointCommission.

12. Closure of the Fund. -

(1) The Fund shall remain operative so long as the relevant provisions of the Act remain in force.

(2) At the time of closure of the Fund, when the fund is no longer required, all the unspent balance under

the fund shall be remitted into the Government Treasury.

[F. No. 47/1/2009-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

ANNEXURE – I

Revised Estimates of (Current Year)/

Budget Estimates of (Next Year)

(See rule 8)

Head of Account	Actuals Last two Years		Budget Allotment	Actuals of first 6 months (prev 2 years and FY)			Actuals for the last 6 months (prev 2 years)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Estimate last 6 months (FY)	Total Revised Estimate	Budget Estimate	Difference between Allotment & RE (11-4)
10	11	12	13

Difference between (BE & RE) (12-11)	Reasons for Variation
14	15

Note1 : Heads of Account shall be as per list at Appendix A

Note 2 : Budgetary provisions shall be explained with detailed memoranda as listed at Appendix B.

ANNEXURE – II

Final Grant Statement (Financial Year)

(See rule 8)

Head of Account	Revised Allotment received	Actuals of first 10 months	Requirement last 2 months	Total Final Grant	Net Savings/ Excess	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Note 1 : Heads of Account shall be as per list at Appendix A.

Note 2 : Budgetary provisions shall be explained with detailed memoranda as listed at Appendix B.

Appendix A

Detailed Heads of Account (with description) under which Joint Commission shall furnish budget Statements

and Explanatory Memoranda thereto

A/c Description

Code

REVENUE

2. Fee and Charges

2.1 Fee

2.2 Charges

2.3 Fines

Total

2.4 Others (Specify)

Grand Total

3. Grants

3.1 From Government

3.2 From others

Total

4. Gifts

5. Seminars and Conferences

6. Sales of Publications

7. Income on Investments and Deposits

7.1 Income on investments

7.2 Income on Deposits

8. Loans

8.1 From Government

8.2 From Others (specify)

9. Sale of Assets

10. Sale of Investments

11. Recoveries from pay bills

11.1 Principal amount of Loans and Advances

11.2 Interest on Loans and Advances

12. Miscellaneous Income

12.1 Gain on sale of assets

12.2 Any Others (specify)

EXPENDITURE

13. Chairperson and Members

13.1 Pay and Allowances

13.2

Other benefits 13.3

Travelling expenses

13.3.1 Overseas

13.3.2 Domestic

14.

Officers 14.1 Pay and

Allowances

14.2 Retirement benefits

14.3 Other benefits

14.4

Travelling expenses 14.4.1

Overseas
14.4.2 Domestic
15. Staff
15.1 Pay and Allowances
15.2 Retirement Benefits
15.3 Other benefits
15.4 Travelling expenses
15.4.1 Overseas
15.4.2 Domestic
16. Hire of Conveyance
17. Wages
18 Overtime
19. Honorarium
20. Other Office Expenses
21. Expenditure on Research
22. Consultation fee
23. Seminars and Conferences
24. Publications of the Joint Commission
25. Rent and Taxes
26. Interest on Loans
27 Promotional Expenses
28. Membership fee
29. Subscription
30. Purchase of fixed assets
31. Investments and Deposits
31.1 Investments
31.2 Deposits
32. Security Deposits
33. Loans and Advances
33.1 To employees
33.1.1 Bearing Interest
33.1.2 Not-bearing interest
33.2 To Suppliers and Contractors
33.3 Others (to specify)
34. Repayment of Loans
35. Others
35.1 Leave salary and pension contribution
35.2 Audit fee
35.3 Miscellaneous
36. Depreciation
37. Loss on sale of assets
38. Bad debt written off
39. Provision for bad & doubtful debts
Total

Appendix B

Explanatory Memoranda to RE/BE Statements of

the Joint Commission for the States of Manipur and Mizoram

1. Statement showing grade-wise details of establishment with provision sought therefor in the estimates,

with actual establishment strength and cost thereof in previous year.

2. Estimates of individual projects/consultancies costing over Rs. 5 lakhs indicating original cost, revisions if any and provisions sought for the project in the budget grants.

3. Details of Foreign exchange component in the Budget/Revised estimates.

4. Estimates of Revenue Receipts in Budget Year and previous year.

5. Statement showing financial results of the Joint Commission for the budget year and previous year.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.